राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDERSS

प्रधान मन्त्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : मुझे इस बात की खुशी है कि अनेक सदस्यों ने इस बात को स्वीकार किया है कि राष्ट्रपति का यह अभिभाषण हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक नये अध्याय की शुरूआत है। विरोधी पक्ष की ओर से उसी प्रकार के भाषण हुए है जैसी की आशा थी हमने आलोचना का हमेशा स्वागत किया है। राष्ट्रपति जी ने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है।

हम जहां एक ओर अपने देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहां दूसरी ओर प्रौद्योगिकी बदलती जा रही है और यह समस्त संसार में उथल पुथल कर रही है। हमें इस बात को नही भूलना चाहिए कि आगामी वर्षों में हमारे जो निर्णय हो, वे नवयुवकों को स्वीकार होने चाहिए।

मुझे विरोधी पक्ष के नेता के भाषण से निराशा हुई है। यह आशा थी कि विरोधी पक्ष के औपचारिक नेता के बच जाने से वाद-विवाद के स्तर में कुछ अन्तर आयेगा और संसदीय परम्परायें मजबूत होंगी परन्तु यह आशा पूरी नहीं हुई है। उनका भाषण में दूरदर्शिता और वास्तविकता का अभाव है। उनके प्रत्येक शब्द में असंतोष झलकता है।

हाल की घटनाओं ने इस बात को चरितार्थ कर दिया हैं कि प्रगतिवादी और रूढ़वादी लोगों के बीच कितना अन्तर है। इस वाद-विवाद से एक जैसे विचारों वाले व्यक्तियों का पता चलता है।

श्री पाटिल ने मुझे एक कैदी की संज्ञा दी है उन्होंने नारों की बात कही है। लेकिन थोड़े लोगों ने नारों का अधिक प्रयोग किया है।

श्री पाटिल एक स्पष्टवक्ता व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी वास्तविक राय को कभी नहीं छिपाया है। उनके राष्ट्रीकरण, समाजवाद और निजी थैलियों सम्बन्धी विचारों से उनके अपने ही पक्ष के समस्त व्यक्ति सहमत नहीं हैं। सभा और सरकार को उपदेश देने से पहिले वह अपने साथियों को अपने विचारों से सहमत करायें। मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि काफी संख्या में भूतपूर्व नरेश ने सामाजिक एकता लाने में उत्साह और दूरदर्शिता का परिचय दे रहे हैं जैसा कि उन्होंने देश की राजनैतिक एकता में परिचय दिया था।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सबसे अधिक हर्षध्वनि निजी थैलियों और विशेषाधिकारों की समाप्ति का उल्लेख करते हुए हुई थी।

कुछ सदस्यों ने अन्तर्राज्यीय सीमा विवादों का उल्लेख किया है। आयोगों की स्थापना का ध्येय तथ्यों और विचारधाराओं का पता लगाना होता है जिससे उनकी सिफारिशों के आधार पर न्यायोचित निर्णय किये जा सकें। हमारे राज्यों के बीच सीमा सम्बन्धी विवाद अनेक ऐतिहासिक कारणों से पैदा हुए हैं। ये कारण सब मामलों में एक जैसे नहीं है।

माननीय सदस्य को पता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की अनेक सिफारिशों को या तो काफी सीमा तक बदलना पड़ा है अथवा उन्हें स्वीकार नहीं किया गया है, परन्तु इन सब मामलों में मुख्य ध्येय यही था कि सम्बन्धित व्यक्तियों को अधिक से अधिक संतुष्टि की जाय । इस सम्बन्ध में कुछ आधारभूत सिद्धान्त बनाने की मांग भी की गई थी । परन्तु इनके लिये कुछ सामान्य नियत बनाना ठीक प्रतीत नहीं होगा । इनका निपटारा तो इनके अपने तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए ।

इसी सभा में और बाहर भी यह कहा गया है कि मैं राजनैतिक प्रयोजनों के लिये सरकारी कर्मचारियों की सेवा प्राप्त करने की योजना बना रही हूँ। मैंने इस बात का बार-बार खंडन किया है और सरकारी कर्मचारियों के बारे में मेरी टिप्पणी को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया है । मेरा हमेशा यह विचार रहा है कि सरकारी कर्मचारी बिना किसी भय अथवा पक्षपात के अपने निर्णय करें और निर्भीक तथा सही सलाह दें । इन कर्मचारियों को जनता की सेवा तथा उसके कल्याण के लिए कटिबद्ध रहना चाहिये । उन्हें हमारे संविधान के मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा संसद द्वारा अपनाये गये उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान रहना चाहिये ।

मैंने देखा है कि असैनिक सेवाओं में सब स्तरों पर आदर और कर्तव्य परायणता का अभाव नहीं है ।

सरकार की बढ़ती हुई जिम्मेदारी को देखते हुए हमें अधिक कार्य कुशलता, अधिक दक्ष जानकारी और कार्य पूरा करने के शीघ्र तरीकों की ओर ध्यान देना चाहिए ।

अनेक माननीय सदस्यों ने 'ऐले' नायक फ्रांसीसी पत्रिका के साथ कुछ महीने पहिले हुए मेरे साक्षात्कार का उल्लेख किया है । उन्होंने शायद साक्षात्कार के मौलिक वार्तालाप को नहीं पढ़ा है अपितु उसके अनुवाद का उल्लेख किया है । ऐसा प्रतीत होता है कि जिस महिला ने मेरे साथ भेंट वार्तालाप किया था उसने इस बारे में भ्रामक स्थिति पैदा कर दी है । जो उसने लिखा है वह उसका अपना विचार है, जिसके बारे में उसने यह समझा है कि मैंने वैसा कहा है । उसने यह भी कहा बताते हैं कि मैंने उससे कहा था कि गांधी जी दिल्ली की अपनी यात्राओं के दौरान आनन्द भवन में ठहरते थे । इन साक्षात्कारों में कभी-कभी लोगों को भ्रम हो जाता है । पत्रिकाओं में विचारों को तोड़ मरोड़ कर रखना तो एक आम बात हो गई है विशेषकर विरोधी पक्षों के सदस्यों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकाओं में गांधी शताब्दी वर्ष में मैंने लगभग प्रत्येक आम सभा में गांधी जी का उल्लेख किया है घोर संकट के समय उन्होंने देश को जो प्रेरणा दी और उसका मार्गदर्शन किया, उसके लिये उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है । मैंने इस सभा में उन्हें देश की महानतम क्रान्तिकारी बताया है । मैंने उन्हें कभी भी प्रतिक्रियावादी नहीं कहा । ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती ।

आचार्य कृपलानी ने श्री ऋत्विक पाठक को पद्म श्री की उपाधि दिये जाने का उल्लेख किया है, श्री पाठक एक चलचित्र निर्माता हैं और अधिकांश भारतीय और विदेशी फिल्म समीक्षकों ने उन्हें एक महान रचनात्मक चलचित्र निर्माता माना है । किसी कलाकार का सम्मान उसकी कला के लिये किया जाता है । श्री पाठक ने कुछ दिन पहिले सार्वजनिक रूप से कहा

है कि वह मानसिक रूप से अत्यधिक परेशान थे जिसके कारण उनके मुख से ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण शब्द निकल गये थे। गांधी जी की महानता इस प्रकार के शब्दों से कम नहीं हो सकती।

आर्थिक नीति के बारे में मैं आज विस्तारपूर्वक नहीं कहूँगी कि क्योंकि इस पर बाद में आय व्यय का और योजना पर विचार करते समय चर्चा होगी। परन्तु मैं उन कुछ बातों को बारे में उल्लेख करना चाहूँगी जो मेरे विचार से गलत धारणाओं और आंकड़ों पर आधारित है।

प्रोफेसर रंगा को यह सन्देह है कि जिस इस्पात को हम तैयार करने की योजना बना रहे है उसकी मांग भी होगी या नहीं। उनका शायद यह विचार कि इस्पात और अन्य इंजीनियरिंग परियोजनाओं की माग में अब भी मन्दी की प्रवृत्ति चल रही है। 1964 और 1968 के बीच इस्पात की मांग में कमी हो गई थी परन्तु उसके बाद धीरे-धीरे काफी बृद्धि हुई है। यह तो सबको पता ही है कि विभिन्न प्रकार के इस्पात की, जैसे बिलट चादर प्लेट और तार की छड़ों की काफी कमी है। इस्पात के अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के बारे में निर्णय लेते समय हमें न केवल आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है बल्कि उसकी दूर भविष्य में होने वाली मांग को भी ध्यान में रखना है। एक इस्पात कारखाने की योजना उसका डिजाइन बनाने तथा उसको निर्धारित क्षमता के अनुसार चलाने में एक से सात वर्ष का समय लगता है। यही कारण है कि हमने बोकारो तथा अन्य इस्पात कारखानों के बिस्तार तथा नई क्षमताओं को बढ़ाने का निर्णय किया है। मैं श्री रंगा से यह अनुरोध करती हूं कि वह इस्पात कारखानों की मांग करने वाले विभिन्न राज्यों को इस बात के लिये मनायेंगे।

श्री मोरारजी देसाई ने बोकारो की पूंजीगत लागत 2860 रुपये प्रतिटन आंकी है किन्तु वह 900,000 मीट्रिक टन लोहे के ढेले के अतिरिक्त उत्पादन का हिसाब लगाना भूल गये हैं। पूंजीगत लागत में वृद्धि होने के कारण कुछ और ही थे। यदि तैयार इस्पात की प्रति टन के हिसाब से विनियोजित पूंजी के आधार बनाया जाये, तो इसी एक बात के आधार पर बोकारो की लागत 10 प्रतिशत कम हो जाती है, और इस प्रकार रूरकेला में प्रति मीट्रिक टन पर 2750 रुपये लागत आयेगी जबकि बोकारो में यह लागत 3100 रुपये प्रति मीट्रिक टन है। दूसरी बात जो श्री देशाई ने कही है वह यह है कि 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीकरण के बाद भी स्थिति नहीं सुधरी है। उनका यह अनुमान बिल्कुल गलत है।

जहां तक रोडेशिया का सम्बन्ध है, भारत सरकार रोडेशिया के अपने आपको पृथक गणतन्त्र घोषित करने के कार्य को अवैध मानती है। तथा इस सम्बन्ध में विश्व-समुदाय और अफ्रीकी राज्य जो कार्यवाही करेंगे। उसका हम समर्थन करेंगे। हम चाहते हैं कि वहां बहु-जातीय समाज में 'एक व्यक्ति एक राय' का सिद्धान्त क्रियान्वित हो। वहां पर अल्प संख्या की बजाय बहुमत का शासन हो।

हमारे सामने मुख्य प्रश्न यह है कि हम किस प्रकार के समाज की स्थापना करना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि समाज में सबको समान अधिकार प्राप्त हों और देश में लोग ऊंच नीच और छोटेपन या बड़ेपन को महसूस न करें। यदि लोगों को समान बनाना है, तो कुछ कार्य तो करने ही होंगे। अन्यथा लोगों के समान अधिकार दिलाने और उन्हें समान बनाने का

स्वप्न कैसे पूरा होगा। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि भारतीय संस्कृति, इतिहास तथा जीवन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए भारतीय ढंग से ही भारतीय समस्याओं को हल करने की आवश्यकता है। अतः हमारे तरीके वे नहीं है जो माननीय सदस्य के हैं। श्री वाजपेयी और उनका दल भारतीयकरण की बात करता है। यदि जनसंघ चाहता है कि प्रत्येक भारतीय अपने देश को प्रेम करे और वह देशभक्त बनें, तो इसमें किसी का भी विरोध नहीं है, परन्तु उसके लिए अलग से भारतीय करण के सिद्धान्त को प्रतिपादित करने की क्या आवश्यकता है शायद श्री वाजपेयी इसका निर्णय स्वयं करना चाहते हैं कि कौन भारतीय है और कौन नहीं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (बलराम पुर) : ऐसी बात नहीं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : माननीय सदस्य चाहते हैं कि कौन भारतीय हैं और कौन नहीं, इसका निर्णय करने के लिए एक न्यायाधिकरण बैठाया जाये ? क्या जनसंघ दल स्वयं इस बात का निर्णायक बनना चाहता है ? ऐसा करने से देश पर उतनी ही भारी विपत्ति आ जायेगी जितनी की अमेरिका में उस समय आई थी जब कि कुछ अमेरीकियों ने अन्य अमेरिका निवासियों को गैर-अमरीकी घोषित कर दिया था। इससे तो लोकतन्त्र का आधार ही समाप्त हो जायेगा आधुनिकतम राष्ट्रीकरण का ही दूसरा नाम भारतीयकरण है और अपने आप में यह आवरणमय प्रतिक्रिया है यदि 'भारतीयकरण' पद बहुत ही सरल है, जैसा कि उसके व्याख्यान कहते हैं, तो उसको इतने जोर के साथ कहने की क्या आवश्यकता है और उससे हमारे कुछ लोगों के मन में भय उत्पन्न क्यों होता है ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : चूंकि भारतीयकरण की ओट लेकर अल्पसंख्यकों को गुमराह करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार किया जा रहा है, मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि प्रधान मन्त्री भारत की एकता में विश्वास नहीं रखती और वह भारत का और भी विभाजन करना चाहती हैं।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : पहले प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का ही भारतीयकरण किया जाना चाहिये।

Shri Atal Bihari Vaspayee : Sir she was not in the House when I delivered my speech. I doubt that she has read my speach. She was not been replying to the points raised to me. Instead she has been trying to put certain things into my mouth, This is wrong.

श्रीमती इन्दिरा गांधी : श्री वाजपेयी जी ने जो कुछ कहा था उस पर मैंने गम्भीरता पूर्वक विचार किया है। किसी भी वक्तव्य के ठीक या गलत होने की कसौटी यह है कि उसके *प्रति उसको सुनने वालों की प्रतिक्रिया क्या होती है।*

श्री बलराज मधोक : आपकी दृष्टि से उसका अन्य लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मेरे लिये प्रत्येक बच्चा जो भारत में पैदा होता है, भारतीय है। भारत में ऐसे कानून विद्यमान हैं जिनके आधार पर यह मूल्यांकन किया जा सकता है कि

कौन व्यक्ति देशद्रोही है। इस बात का निर्णय किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस बात का निर्णय किसी राजनीतिक दल द्वारा भी नहीं किया जा सकता। जो लोग भारतीयकरण के सिद्धान्त का प्रचार कर रहे हैं, उनके इरादे छिपे नहीं रह सकते अतः भारतीयकरण का बार बार उल्लेख करना वांछनीय नहीं है।

श्री वाजपेयी के भाषण के समय मैं यहाँ पर उपस्थित नहीं थी परन्तु मैंने उनका भाषण पढ़ा है, सुन्दर वाक्यों में उग्रवादी इरादे छिपे होते हैं, चाहे वे दक्षिणपंथी हों अथवा वामपंथी। उनके दल द्वारा एक स्वदेशी योजना का प्रचार किया जा जा रहा है जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय से हाल में वापस आये तब अर्थशास्त्री के दिमाग की उपज है। यह ऐसी रूपरेखा है, जिसमें बहुत बड़े-बड़े वायदे दिये गये हैं, परन्तु यह नहीं बताया गया कि उन वायदों को किस प्रकार पूरा किया जायेगा। अन्य बातों के अतिरिक्त इसमें परमाणु अस्त्रों के संग्रह के लिए धन जुटाने के कार्यक्रम का भी वचन दिया गया है।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : क्या वे वचन देंगी कि वे राष्ट्रपति हित को ध्यान में रखते हुए परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकने सम्बन्धी संधि, जिस पर कल हस्ताक्षर किये जाने हैं, को स्वीकार करने से इन्कार कर देंगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह योजना हवा में रस्सी खड़ी करने वाले भारतीय जादू के समान है। जिसकी चर्चा तो बहुत है, परन्तु जिसे किसी ने देखा नहीं है। क्या श्री वाजपेयी बतायेंगी की उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त की 50 प्रतिशत राशि बचाने के लिये लोगों को किस प्रकार बाध्य किया जाता सकता है ? यदि विदेशों से सहायता लेनी बन्द कर दी जाये तो इतना विशाल कार्यक्रम किस प्रकार क्रियान्वित किया जा सकता है ? इसके लिये कहां से धन आयेगा ? यदि इस योजना पर शांति और गम्भीरता से विचार किया जाये, तो निराशा ही हाथ लगेगी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि श्री वाजपेयी के दल के दिमाग में एक भिन्न प्रकार के सामाजिक और राजनैतिक धारणायें है, जो हमारी व्यवस्था से बाहर है। इस योजना में सामाजिक व्यवस्था के एक एकाधिकारी भावना है और लोकतन्त्रीय सामाजिक व्यवस्था के साथ यह मेल नहीं खा सकती है।

श्री मोरार जी देसाई ने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में उज्जैन में तथा दूसरे सदन में दिये गये मेरे भाषण का उल्लेख किया है। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हम सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ण सम्मान करते हैं, वास्तव में न्यायाधीश का देश में सभी को सर्वाधिक सम्मान करना चाहिए। सरकार तीनों अंगों को विधान मण्डल, कार्यपालिका और न्यायपालिका को, संविधान को सर्वोपरि रखने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा हैं। परन्तु संविधान में कुछ निदेशात्मक सिद्धान्त दिये गये हैं, जिनकी विवेचन के बारे में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। जबकि हमारा कोई अधिनियम अवैध ठहराया गया है, हमने सविधान के ढाचे के अन्दर रहते हुए उपचारात्मक कार्यवाही की है।

गत वर्ष ऐसा प्रतीत हुआ था कि कुछ दिशाओं में भारत में परिवर्तन की गति धीमी पड़ी गई है। इससे अनेक लोगों में विशेष रूप से नवयुवक पीढ़ी में असंतोष बढ़ गया था अब फिर

हम प्रगति की ओर तेजी से बढ़ने लगे हैं। यह मेरी अटूट निष्ठा है कि भारत की समस्याओं को हल करने का एक मात्र मार्ग लोकतन्त्रीय मार्ग है। लेकिन समाजवाद और धर्म-निरपेक्षता के बिना सच्चा लोकतन्त्र नहीं हो सकता है। इस आदर्श को सामने रखकर ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 से 30 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 1 to 30 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 31 और 32 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 31 and 32 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 33 से 39 और 365 से 368 तक मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

Amendment Nos. 33 to 39 and 365 to 368 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 52 मतदान के लिये रखा गया.

Amendment No. 52 was put.

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 73 ; विपक्ष में : 207.

Ayes : 73 ; Noes : 207

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

The amendment was negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 51, 53, 54 और 55 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 51, 53, 54 and 55 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 56 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 56 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 66 और 461 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 66 and 461 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 92 मतदान के लिये रखा गया

Amendment No. 92 was put.